प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 19 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 06 – 13 मई 2019 मूल्य पांच रूपए

शाह के मुताबिक मोदी ने हिमाचल को 2,30,000 करोड़ दिया तो जयराम सरकार कर्ज क्यों ले रही है

शिमला/शैल। हिमाचल का चुनाव अन्तिम चरण में है। 2014 में भाजपा ने प्रदेश की चारों सीटों पर

जीत हासिल की थी। इस बार भी इस जीत को बरकरार रखने की चुनौती है। इस चुनौती को पूरा करने के लिये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमितशाह ने भी हिमाचल को समय दिया है। मोदी मण्डी और सोलन में रैलियां कर गये हैं। अमितशाह की रैलियां चम्बा बिलासपुर और सिरमौर में हुई हैं। अमितशाह ने अपनी रैलियों में आकड़े रखते हुए दावा किया है कि मोदी सरकार ने हिमाचल को 2,09,031 करोड़ दिये हैं। जबकि कांग्रेस ने 44235 करोड़, दिये थे। इसके अतिरिक्त एम्ज़, आई.आई.एम. और पर्यटन के लिये 2000 करोड़, बागवानी के लिये 1800, सड़क विस्तार के लिये 770, कृषि विकास के लिये 709 और रेलवे के लिये 15000 करोड़ दिये हैं। यदि इन सारे आंकड़ो को जोड़ा जाये तो यह राशी 20,009 करोड़ बनती है। शाह की रैलीयों के बाद भाजपा द्वारा प्रैस नोट में भी इन आंकड़ो का वाकायदा जिक्र है। यह आंकड़े आने के बाद यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब मोदी सरकार ने हिमाचल को अब तक 2,30,000 करोड़ दे दिया है तो फिर जयराम सरकार कर्ज क्यों ले रही है। क्योंकि अभी नये वित्त वर्ष के पहले ही महीने में प्रदेश सरकार ने 1100 करोड़ का कर्ज लिया है। यदि शाह द्वारा अपनी रैलीयों में परोसे गये आंकड़े सही हैं तब तो यह सवाल उठता है कि क्या जयराम सरकार कर्ज लेकर कोई बड़ा घोटाला कर रही है। क्योंकि शाह ने साफ कहा कि मोदी सरकार ने प्रदेश सरकार को यह पैसा दिया है जब केन्द्र सरकार ने यह पैसा दिया है तो निश्चित रूप से सरकार के खजाने में यह पैसा आया है और जब यह पैसा आया है तो जयराम सरकार को हिसाब भी प्रदेश की जनता के सामने रखना होगा।

जयराम सरकार कर्ज के सहारे चल रही है यह सार्वजनिक हो चुका है। प्रदेश का वित्त विभाग शाह द्वारा परोसे गये आंकड़ो की पुष्टि नही कर रहा है और यह पुष्टि न करने का अर्थ है कि यह आंकड़े पूरी तरह गलत हैं और केवल चुनावी लाभ लेने के लिये परोसे गये हैं ताकि प्रदेश की जनता इन पर विश्वास कर ले। क्योंकि मीडिया तो इन आंकड़ो की प्रमाणिकता की छानबीन करेगा नही और उसके ऐसा न करने के अपने कारण हैं। इन वित्तिय आंकड़ो की तरह ही प्रदेश को मिले 69 राष्ट्रीय राजमार्गो की स्थिति यह आंकड़े भी प्रदेश की जनता को लम्बे अरसे से परोसे जा रहे हैं। बल्कि राजमार्गो का खुलासा तो केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा और नितिन गडकरी के बीच हुए पत्रचार के माध्यम से किया गया था। बल्कि जयराम के मन्त्री सैजल ने तो एक ब्यान में यहां तक कह दिया है कि इन राजमार्गो की डीपीआर अब तैयार करवाकर गडकरी से शिलान्यास भी करवा दिया है। जबकि प्रदेश उच्च न्यायालय में इन राजमार्गो को लेकर आयी एक याचिका पर जवाब दायर करके केन्द्र सरकार ने स्पष्ट मान लिया है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक सैद्धान्तिक स्वीकृति के स्तर पर ही हैं।

इन आंकड़ो से स्पष्ट हो जाता है कि चुनावी लाभ लेने के लिये नेता जनता में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन क्या जनता भी मन्त्रियों/नेताओं के परोसे आंकड़ो पर वैसे ही विश्वास कर लेती है जैसे यह बोलकर जाते हैं। शायद जनता विश्वास नही करती है और इसलिये हर भीड़ वोटर में तबदील नही होती है। आज की जनता नेता के ब्यानों की असलियत जमीन पर परखती है आज की जनता को पाकिस्तान और मुस्लिम का डर दिखाकर जयादा देर तक गुमराह नही किया जा सकता है। इसलिये यह माना जा रहा है कि जिस तरह हिमाचल की जनता ने 2014 में मोदी-भाजपा पर विश्वास करके चारों सीटें भाजपा को दे दी थी वैसा शायद इस बार नही हो पायेगा क्योंकि आज मोदी और शाह की विश्वनीयता पर ही सबसे अधिक प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं बल्कि शाह के परोसे आंकड़ो से जयराम और उनकी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि इन आंकड़ो को यदि सरकार सही ठहराती है तो उसे जनता को यह बताना पड़ेगा कि वह कर्ज क्यों ले रही है।

अदाणी प्रकरण में महाधिवक्ता को निर्देश किसने दिये खड़ा हुआ विवाद

प्रधान सचिव ने मुख्यमन्त्री को भेजी फाईल

शिमला/शैल। अदाणी पावर ने हिमाचल सरकार से 280 करोड़ रूपये 18% ब्याज सहित वापिस लेने के लिये प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर रखी है। 2019 में दायर हुई इस याचिका पर उच्च न्यायालय में दो बार पेशी लग चुकी है पहली बार लगी पेशी में उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिये थे कि वह यह बताये कि उसने इस परियोजना को आवंटित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं। अदाणी पावर के 280 करोड़ वापिस करने का जो वायदा सरकार ने कर रखा है वह पूरा हो सके। उच्च न्यायालय में यह आदेश 19 मार्च को हुआ था। इसके बाद यह मामला 26 अप्रैल को फिर अदालत में लगा और तब प्रदेश के महाधिवक्ता ने अदालत को यह बताया कि सरकार इस मामले को पुन: विचार के लिये मन्त्रीमण्डल में ले जायेगी। इस समय आचार संहिता लागू होने के कारण मन्त्रीमण्डल की बैठक नही हो सकती है इसलिये इसमें और समय दिया जाये। महाधिवक्ता के आग्रह पर अदालत ने और समय देते हुये अगली सुनवाई 20 जून को तह की है

महाधिवक्ता के आग्रह पर अदालत ने और समय दे दिया है लेकिन इसी के साथ इस मामले को पुन: मन्त्रीमण्डल में ले जाने की बाध्यता भी बन गयी है। स्मरणीय है कि अदाणी पावर के 280 करोड़ वापिस करने का फैसला सरकार ने 2015 में लिया था। इस फैसले से अदाणी को अवगत भी करवा दिया था। लेकिन दिसम्बर 2017 में सरकार ने इस फैसले को फिर बदल दिया और अदाणी को फिर सूचित कर दिया कि कुछ जटिलताओं के चलते सरकार को यह फैसला बदलना पड़ रहा है। अब अदानी इस मामले को 2019 में प्रदेश उच्च न्यायालय में ले गये हैं। जहां इस पर सुनवाई चल रही है।

हिमाचल सरकार ने 2006 में 960 मैगावाट की जलविद्युत परियोजना जंगी थोपन और पावरी के लिये निविदायें आमन्त्रित की थी। इन निविदाओं के आधार पर यह परियोजना निष्पादन के लिये नीदरलैण्ड की एक कंपनी ब्रेकल को आवंटित कर दी थी। लेकिन जब ब्रेकल तय समय के भीतर 280 करोड़ का अपफ्रन्ट प्रिमियम अदा नही कर पायी तब इसमें निविदाओं में दूसरे स्थान पर रही रिलांयस ने अपना दावा जता दिया। रिलायंस इसमें उच्च न्यायालय में चला गया। उच्च न्यायालय ने 7 अक्तूबर को यह आवंटन रद्द कर दिया और सरकार को इसमें नये सिरे से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये। 2006 से यह परियोजना विवादो में चल

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राजभवन में मनाया गया विश्व रैडक्रास दिवस

शिमला/शैल। राज्यपाल एवं हिमाचल प्रदेश राज्य रैडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष आचार्य देवव्रत ने प्रदेश के लोगों को रैडक्रास के कार्यों में भाग लेने तथा समाज के कल्याण के लिए निःस्वार्थ भाव व आपसी सहयोग से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता के कल्याण में की गई सेवा भगवान की सेवा ही है।

राज्यपाल राजभवन में विश्व रैडक्रास दिवस पर राज्य रैडक्रास शाखा द्वारा आयोजित रैडक्रास रैली को हरी झण्डी दिखाने के उपरान्त सम्बोधित कर रहे थे। रैडक्रास सोसायटी के सदस्यों व स्वयंसेवकों तथा विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने राज्यपाल तथा लेडी गवर्नर दर्शना देवी को विश्व रैडक्रास दिवस पर रैडक्रास ध्वज लगाए। राज्य रैडक्रास अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा एवं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थी।

विश्व रैडक्रास दिवस, रैडक्रास के संस्थापक जीन हैनरी डुनेंट की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2019 में विश्व रैडक्रास दिवस का विषय 'वट डू यू लव अबाउट रैडक्रास' है।

राज्यपाल तथा लेडी गवर्नर ने रैडक्रास कोष के लिए भी दान दिया तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला व लालपानी, शिमला के विद्यार्थियों को मिठाइयां बांटी।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि

रैडक्रास संस्था हमें मानवता तथा निःस्वार्थ भाव से सेवा करने का सन्देश देती है। यह खुशी की बात है कि इस संस्था की शाखाएं देशभर में निर्धन व पीड़ित मानवता की ईमानदारी से सेवा कर रही है।

राज्यपाल ने प्रदेश के लोगों से रैडक्रास के आन्दोलन के लक्ष्यों को सुदृढ़ करने तथा संस्था के सदस्यों व स्वयंसेवकों को सम्पूर्ण सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मानवता की पीड़ाओं को मिटाने के लिए सभी के लिए जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा तथा सहायता के लिए एकजुटता की भावना से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने रैडक्रास की गतिविधियों को जन आन्दोलन बनाने के लिए और लोगों को जुड़ने की अपील की।

राज्यपाल के सचिव एवं राज्य रैडक्रास के महासचिव राकेश कवंर, राज्य रैडक्रास सचिव पी.एस. राणा, रैडक्रास अस्पताल कल्याण सोसायटी की अवैतनिक सचिव पूनम चौहान, रैडक्रास अस्पताल कल्याण सोसायटी की उपाध्यक्षा फिरोजा विजय सिंह तथा उपाध्यक्ष डॉ. कविता मरडी तथा रैडक्रास अस्पताल कल्याण सोसायटी के कार्यकारी सदस्य भी इस अवसर पर अन्य सहित उपस्थित थे।

सोलन के 10 मतदान केंद्रों की कमांड महिला कर्मियों के पास

शिमला/शैल। 19 मई को लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में जिले के 10 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों के तौर पर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनोद कुमार ने बताया कि सोलन जिला के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के तहत 10 मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है जहां महिला कर्मी अपना दायित्व निभाएंगी।

उन्होंने बताया कि जिन मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों की नियुक्ति की गई है उनमें अर्की विधानसभा क्षेत्र के तहत अर्की-3 और बातल-1, नालागढ़ के तहत वार्ड नंबर-9 नालागढ़ और वार्ड नंबर-4 नालागढ़, दून के तहत कौंडी और दसोमाजरा, सोलन के तहत सोलन वार्ड नंबर 7(2) और सोलन वार्ड नंबर 10(1) जबकि कसौली विधानसभा क्षेत्र के तहत कीमुघाट(कसौली-2) और कसौली -3 शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1155 मतदाता अर्की-3 में हैं। जबकि सबसे कम 435 मतदाता कसौली-3 के तहत हैं।

टिपरा (परवाणू) से शालाघाट तक नो पार्किंग जोन घोषित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-5 पर जिला सोलन में टिपरा से शालाघाट तक के सड़क मार्ग को 'नो पार्किंग जोन' घोषित कर दिया है। यानि सड़क के किनारे किसी भी प्रकार के वाहन पार्क नही किए जा सकेंगे ।

उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी सोलन विनोद कुमार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 व 117, रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशंस 1989 के नियम 15 और हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स 1999 के नियम 184 व 196 के तहत इस आशय को लेकर जारी आदेश के मुताबिक टिपरा (परवाणू) से शालाघाट तक के इस हिस्से पर किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग प्रतिबंधित कर दी गई है। इस आदेश से एंबुलेंस, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन सेवाओं के अलावा कानून एवं व्यवस्था से जुड़े वाहनों को मुक्त रखा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग की फोर लेनिंग के निर्माण कार्य में लगी मशीनरी भी इस आदेश से मुक्त रहेगी। आदेश में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आदेश की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

शूलिनी मेला में काऊ शो के लिये पशुपालन विभाग अपनी कार्य योजना तैयार करे:उपायुक्त

सोलन/शैल। सोलन का ऐतिहासिक और प्रसिद्ध शूलिनी मेला 21 से 23 जून तक आयोजित किया जाएगा। मेले के प्रबंधों पर चर्चा को लेकर मेला आयोजन समिति की उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि शूलिनी मेले का आगाज 21 जून को पारंपरिक धार्मिक रस्मों के साथ होगा। उन्होंने कहा कि शूलिनी मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचली कलाकारों को तरजीह दी जाएगी ताकि जहां हिमाचली लोक कलाकारों को मंच मिले वहीं हिमाचल प्रदेश की विविध लोक संस्कृति की झलक लोगों को देखने को मिल सके।

उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक संध्याओं की व्यापक रूपरेखा को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श मेले की सांस्कृतिक उपसमिति द्वारा भी किया जाएगा। उपायुद्र ने मेला आयोजन समिति के गैर सरकारी सदस्यों से भी आग्रह किया कि वे मेले के आयोजन को और बेहतर और आकर्षक बनाने को लेकर अपने सुझाव अवश्य दें। उन्होंने कहा कि मेले में स्थापित होने वाली प्रदर्शनी में बेहतरीन गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला मंडलों के स्वयं सहायता समूह के स्टालों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनके उत्पाद इन स्टालों के माध्यम से प्रदर्शित भी हों और उन्हें मार्केट की सहूलियत मिल सके। मेले के दौरान विभिन्न तरह के शो आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि डॉग शो और फ्लावर शो के अलावा काऊ शो करवाए जाने की दिशा में पशुपालन विभाग अपनी कार्य योजना तैयार करे ताकि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को मौका मिल सके कि वे अपनी पालतू गायों को इस शो के माध्यम से प्रदर्शित कर सकें।

उन्होंने कहा कि इस शो के आयोजन का मकसद पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे ग्रामीण आर्थिकी से जुड़े पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण व्यवसाय को आने वाली पीढ़ियों तक भी लेकर जाएं। उपायुक्त ने कहा कि मेले के दौरान पुलिस कानून एवं व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अपने विशेष प्लान के मुताबिक कार्य करेगी। वहीं सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग इस अवधि में पेयजल

की स्वच्छ व समुचित व्यवस्था बनाएगा।

उपायुक्त ने विशेषकर नगर परिषद के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि मेले के दौरान कूड़े कचरे को एकत्र करके उठाए जाने की व्यवस्था पुख्ता एवं प्रभावी बनाई जाए ताकि मेले में गंदगी का आलम ना रहे और स्वच्छता बनी रहे। बैठक में खेलकद स्पर्धाओं और क्राफ्ट मेले के आयोजन के अलावा मेले की स्मारिका के प्रकाशन को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चदेल, सहायक आयुक्त भानु गुप्ता के अलावा मेला आयोजन समिति के अन्य सरकारी और गैर सरकारी सदस्य भी मौजूद रहे।

सिविल स्टेशन धर्मशाला में दो आवेदकों को आवंटित भूमि खारिज

शिमला/शैल। सिविल स्टेशन धर्मशाला में तीन/दो बिस्वा के तहत दो लोगों को आवंटित सरकारी भूमि को खारिज कर दिया गया है। इस बाबत लोगों ने भूमि के आवंटन को नियमों के विपरीत देने की शिकायत जिला प्रशासन से की थी। उपायुक्त कांगड़ा ने इस मामले की जांच एसडीएम धर्मशाला से करवाई जिसमें भूमि आवंटन के लिए निर्धारित न्यूनतम आय सीमा से दोनों ही लाभार्थियों की आय ज्यादा पाई गई उसके आधार पर ही दोनों ही व्यक्तियों को आवंटित भूमि खारिज करके इसे पुनः सरकार में निहित कर दिया गया है।

उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने बताया कि सिविल स्टेशन धर्मशाला में जसवंत राय पुत्र रूप चंद को चार दिसंबर 2018 तथा बंदना देवी पुत्री विशंबर सिंह को 28 नवंबर 2018 को गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन आदेश के खिलाफ वार्ड नंबर सात व दस श्यामनगर के निवासियों द्वारा लिखित शिकायत में कहा गया था कि उक्त आवेदक इस स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं हैं क्योंकि उनकी वार्षिक आय पचास हजार से अधिक है जो कि पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि इस शिकायत की छानबीन उपमंडलाधिकारी धर्मशाला से करवाई गई जिसमें दोनों ही आवेदकों की आय पचास हजार से अधिक पाई गई। इसी को आधार मानते हुए दोनों ही आवेदकों के पक्ष में आवंटित की गई भूमि को रदद करके सरकार में निहित करने के आदेश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया संवैधानिक दर्जा:डॉ.सैजल

शिमला/शैल। भाजपा नेता व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए संविधान में संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। सोलन से जारी प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का यह एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय है। उन्होंने कहा कि यह आयोग अब सलाहकार नहीं, बल्कि भागीदार की भूमिका में होगा।

राजीव सैजल ने कहा कि यही नहीं मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम को संविधान में संशोधन करके और अधिक सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि समुदायों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की गई है। सैजल ने कहा कि भाजपा सरकारें हमेशा ही समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए तत्पर रही है और विशेषकर समाज के पिछले वर्ग को मुख्यधारा में लाने के जो प्रयास किए हैं निश्चित रूप से कारगार सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जनजातियों की विरासतों को संरक्षित

करने के लिए उनकी पारंपरिक संस्कृति, कलाओं और बोली-भाषाओं के प्रोत्साहन और संवर्द्धन सम्बन्धि गतिविधियों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में संस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार समाज के हर वर्ग का समान विकास कर रही है और ऐसे क्षेत्रों जहां विकास की अत्यन्त जरूरत है उन्हें चिन्हित कर विशेष रूप से केन्द्रित कर वहां विकास की गति को तेज किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। राजीव सैजल ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके नेतृत्व में संसदीय क्षेत्र का विकास नये आयामों को छुयेगा। सुरेश कश्यप इस क्षेत्र से अभूतपूर्व जीत सुनिश्चित करेंगे और केन्द्र में पुनः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाएगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

देश में विपक्ष की कोई तस्वीर ही नहीं:शान्ता कुमार

शिमला/शैल। शिमला में पत्रकार वार्ता में शान्ता कुमार ने कहा कि एक तरफ पिछले पाचं साल के काम जनता के सामने हैं दूसरी ओर विपक्ष की कोई तस्वीर ही नही है। पांच साल विपक्ष की सरकार कौन चलायेगा कोई गठजोड़ नही है। आज यह सही है कि नरेन्द्र मोदी का न कोई विकल्प है और न ही जो काम हमने पिछले पांच वर्षो में किये हैं उनका कोई विकल्प है। इस बार भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा सीटो पर जीत हासिल करेगी है। उन्होने कहा विकास तो हर बार कुछ न कुछ हुआ है पर जमीनी स्तर पर जो कार्य पिछले पांच वर्षो में हुए हैं उसका मुकाबला नही है। उन्होने कहा कि विपक्ष के नेता वीरभद्र सिंह जिस तरह से अपने ही नेताओं के बारे मे ब्यान दे रहे हैं जिसके चलते आनन्द शर्मा और सुक्खु को स्टेज तक छोडना पड़े दूसरी ओर शिमला के उम्मीदवार को पुराना

पापी कहना सुखराम ने मेरे साथ धोखा किया है इस तरह के ब्यान अपने में ही बयां करते है कि हिमाचल में स्वस्थ्य विपक्ष है ही नही। इस समय विपक्ष बिखरा हुआ है चार दिन पहले वीरभद्र जयराम को अच्छा आदमी बताते थे लेकिन आज वह उन्हें शातिर व अपनी खालट़ी से बाहर हो गये हैं इस तरह के ब्यान राजनितिक मजबूरी के कारण देने पड़ रहे हैं इससे साफ झलकता है कि विपक्ष पूरी तरह बिखरा पड़ा हैं।

उन्होने कहा इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जिस तरह से उन्होने उद्योग नीति में परिर्वतन किया है उससे दिल्ली व पूरे भारत के उद्योपतियों में हिमाचल के बारे में आर्कषण बढ़ा हैं। हिमाचल स्वीटजरलैण्ड से कम नही है उसका आज तक हम लाभ नही उठा पाये हैं क्योंकि हम कोई इन्वेस्टर फ्रैंडली उद्योग नीति प्रदेश में ला ही नही पाये। लेकिन इस सरकार ने कुछ अहम फैसले इन्वेस्टरज़ के लिये किये हैं जिसमें अहम है एग्रीमेंट होने के बाद सरकार सभी एनओसी, फॉरेस्ट क्लीरेंस एक निश्चित समय सीमा के अन्दर इन्वेस्टरज़ को मुहया करवायेगी। इस बार सरकार धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टरज मीट कराने के हर सम्भव कर रही है। उन्होंने राजनीति में भाजपा के 75 साल से अधिक उम्र के नेताओं को टिकट न दिये जाने के स्वाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी में नये जवान आगे आने चाहिये। उन्होने नेताओं की भाषा शैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज देश राजनीति का स्तर बनाये रखने की जरूरत है। अभी भी हिमाचल में राजनीति और व्यवहार का स्तर बहुत ऊंचा रहा है।

धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ :रामलाल ठाकुर

शिमला/शैल। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से हमेशा सौतेला व्यवहार करते हुए विकास के नाम पर एक ईंट तक

नही लगाई । यह बात हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने जिला मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव गद्दी धार, टीहरा, घरबासडा, पीपली, जोडन, खैलग लौगणी, भडडार, मण्डप, लुधियाना (पैहड), बरोटी, बनाल, बहरी, सिद्धपुर, स्योह, तनहेड आदि में जन सम्पर्क अभियान के तहत अनेक नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला मंडी के इस विधानसभा क्षेत्र का विकास प्राथमिकता के आधार किया जाएगा। ताकि क्षेत्र के अंतिम छोर तक विकास पहुंच सके। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार भी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से सौतेला व्यवहार कर रही है क्षेत्र को मंत्री पद तो दे दिया लेकिन विकास के नाम पर कुछ नही किया। उन्होंने कहा कि 15 साल तक अनुराग ठाकुर सांसद रहने के बावजूद व बार-बार धर्मपुर को मंत्री पद दिए जाने के बावजूद आज भी इस क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने में नाकाम रहे हैं जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को अपनी पेंशन लेने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की इस बड़ी समस्या को प्राथमिकता के आधार हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने क्षेत्र के विकास को दरकिनार करते हुए मात्र क्रिकेट की तरजीह देते हुए अपने घर को भरने का काम किया। क्षेत्र के युवा वर्ग के लिए रोजगार के कोई रास्ते नही तलाशे गए। युवा वर्ग रोजगार के लिए दर दर भटकते फिर रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सचिव चंद्र शेखर व् अन्य लोग मौजूद थे।

अंतिम संस्कार की लकड़ी का अधिकार तक कांग्रेस पार्टी ने किया था खत्मः प्रवीण शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चुनाव प्रभारी प्रवीन शर्मा ने कहा की कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आई है तब-तब प्रदेश की जनता

को इन्होंने दमनकारी नीतियों से प्रताड़ित किया है और स्वयं सत्ता के मजे लूटे हैं। कांग्रेस की सरकारों में जंगली लकड़ी के उपयोग के लिए जरूरतमंदों को रोक और वन काटुओं को अवैध वन कटान के लिए पूरा पूरा कटान के लिए पूरा पूरा संरक्षण दिया जाता रहा है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जहां हर गांव हर घर हर व्यक्ति को जंगली लकड़ी का उपयोग करने की जरूरत पड़ जाती है वहां पर कांग्रेस की सरकार में आम जनता के टीडी अधिकार तक खत्म कर दिए गए थे। आम व्यक्ति के लिए अंतिम संस्कार की लकड़ी तक का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया था। दूसरी तरफ भाजपा जब भी सत्ता में आती है तो आम जनता के हितों से जुड़े हर छोटे से बड़े मुद्दे को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। 2007 में जब भाजपा की सरकार है इस प्रदेश में बनी थी तब लोगों को डीडी की लकड़ी का अधिकार फिर से दिलाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था।

उन्होंने कहा कि आम जनता को जंगली लकड़ी का इस्तेमाल तक करने से रोकने वाली कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रदेश सरकार में जिस तरह वन काटुओं को पूरा पूरा संरक्षण देते हुए वनों के अवैध कटान को बढ़ावा दिया गया वह किसी से छुपा नही। यहां तक कि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के विरुद्ध उन्ही के पार्टी के तत्कालीन विधायक बंबर ठाकुर ने अवैध वन कटान के आरोप लगाए थे। वन माफियाओं को कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सरकार में कितना संरक्षण मिला हुआ था इस बात का अंदाजा प्रदेश में हुए होशियार सिंह हत्याकांड जैसे किस्सों से लगाया जा सकता है। वन संपदा को बचाने एवं अपनी डडूटी अच्छी तरह निभाने में लगे हुए उस गरीब मां के बेटे को वन माफियाओं के हाथों अपने प्राण गंवाने पड़े, इस तरह का हौसला वन माफियाओं को कांग्रेस की सरकार में मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर से यह सवाल पूछना चाहती है कि वह बताएं कि जो कांग्रेस पार्टी प्रदेश के आम व्यक्ति के टीडी अधिकारों को खत्म कर कर देती है और वन काटुओं को अवैध वन कटान के लिए सरंक्षण प्रदान करती है वह जनता के हितों की सुरक्षा करने का कौन सा तरीका है। उन्होंने कहा कि वन संपदा जहां हमारे प्रदेश की शान है तो वहीं दूसरी और यही वन संपदा एक आम व्यक्ति के रोज रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम भी आती है एक आम व्यक्ति से उसके अधिकार छीनने वाली कांग्रेस पार्टी को लोग माफ नही करेंगे और चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखा कर हिसाब चुकता करेंगे।

देश से मोदी ही भागे गांधी कभी नहीःआश्रय

शिमला/शैल। कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में आश्रय शर्मा मैवी सेरी, गोहर, चच्योट, शाला, धिस्ती, जहल देवी दहड़, बग्गी, पलौहटा व ढाबण व अन्य क्षेत्रों का

दौरा किया इस दौरान आश्रय शर्मा ने कहा कि आज देश की जनता के घरों में जमा धन मोदी सरकार ने बैंकों में रखवा दिया काला धन वापिस लाने के लिए वादा किया 15 लाख हर खाते में डालने का वादा किया लेकिन आज दिन तक किसी को 15 लाख तो नही मिले लेकिन लोगों के घरों में जमा धन बैंको में जरूर पहुंचा दिया और उन बैंको से बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया और वे उद्योगपति लोगों का धन लेकर विदेश भाग गए। आश्रय शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाती आई है लेकिन साबित नही कर पाई लेकिन देश की जनता जानती है आज तक देश से मोदी ही भागे है कोई गांधी देश से नही भागा आश्रय ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री देश की सेवा करते करते शहीद हो गए इंदिरा गांधी व राजीव गांधी देश की सेवा करते करते शहीद हो गए ऐसी हैं कांग्रेस पार्टी लेकिन दूसरी तरफ भाजपा है जो आज जुमला पार्टी बनकर रह गई है ।

सिख नरसंहार के दोषी राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लें: परमजीत सिंह पम्मी

शिमला/शैल। भाजपा नेता एवं दून विधायक सरदार परमजीत सिंह पम्मी ने मांग की है कि देशभर में हजारों सिखों के नरसंहार के लिए जिम्मेवार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी

से भारत रत्न वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतने बड़े अपराध के लिए सिखों और देश से माफी मांगने की बजाए नरसंहार को जायज ठहरा रही है। उन्होंने राहुल गांधी के राजनैतिक सलहाकार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें सिखों के हत्या कांड के बारे में कहा गया था कि 'अगर यह हुआ तो क्या हुआ'।

सरदार परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में पांच हजार से ज्यादा सिखों को 1984 में जिंदा जलाया गया था तब राजीव गांधी ने इसे जायज ठहराते हुए कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती ही है। इस बयान ने कांग्रेसियों को सिखों के हत्याकांड और लूटपाट के लिए उकसाया। राजीव गांधी के इशारे पर पुलिस ने सिखों के हत्यारों के खिलाफ केस नहीं दर्ज किए। जहां पुलिस ने दोषियों पर केस दर्ज किये तो उसे इतना कमजोर बना दिया कि अपराधी बरी हो गये।

दून के विधायक ने कहा कि कांग्रेस को इस पाप के लिए कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नरसंहार के 35 वर्ष बीत जाने के बावजूद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। सिखों के कत्लेआम के एक दोषी कमल नाथ को राहुल गांधी ने इनाम देकर मध्यप्रदेयश का मुख्यमंत्री बना दिया है। कांग्रेस लगातार सिखों के जले पर नमक छिड़क रही है। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी के राजनैतिक सलाहकार सैम पित्रोदा ने बयान दिया कि नरसंहार हुआ तो क्या हुआ। उनके लिए अल्पसंख्यक सिखों की जान कोई मायने नही रखती है।

आपसी तालमेल से सुलझाएं कानूनी मामलेःशर्मा

शिमला/शैल। जिला मुख्यालय मण्डी से लगभग 120 किलोमीटर दूर समामाहू ग्राम पंचायत में एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता आर. के.शर्मा जिला एवं सत्र न्यायधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डी द्वारा की गई। इस अवसर पर पर आर.के.शर्मा ने उपस्थित लोगों का आहवान् किया कि वह हर सम्भव प्रयास करें कि उनके मामले न्यायलय में जाने से पूर्व ही आपसी तालमेल से निपट जाएं। ऐसा करने से जहां वह कानूनी मुकद्दमों पर आने वाले व्यय से बच सकेंगें वहीं ऐसे प्रयासों से भाईचारे की भावना को भी बल मिलता है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य न्यायलय में दायर किये जाने से पूर्व मामलों तथा न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का बिना किसी कानूनी बारीकियों के खर्च व समय को बचाते हुए त्वरित न्याय को सुनिश्चित करना है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अर्पना शर्मा ने महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों बारे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएं समाज के निर्माण में अहंम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न करें क्योंकि शिक्षा मानव जीवन के विकास का अहंम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाना आय एक लाख से कम है वह विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त सलाह ले सकते है। उन्होंने बताया कि कानूनी सहायता के लिए यदि आवेदक अनपढ़ है अथवा लिखने की स्थिति में नही है तो विधिक सेवा प्राधिकरण, समिति के सदस्य सचिव अथवा अधिकारी उसके जुबानी निवेदन को रिकार्ड करेंगें तथा उस पर उसका हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप लेंगे और ऐसा रिकार्ड उस व्यक्ति का आवेदन माना जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण असलम बेग ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, वर्ग विशेष पर अत्याचार, बाढ़, भूकम्प जैसी आपदा से प्रभावित व्यक्ति भी मुफ्त कानूनी सलाह व सहायता प्राप्त कर सकते है। शिविर में प्रधान ग्राम पंचायत समानाहू घनश्याम शर्मा, उप प्रधान जय लाल ठाकुर सहित महिला मण्डल भवनाला, कसयूण, बगलामाहू, टटमोह तथा समाहू के प्रधान व सदस्यों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

जैसे ही भय आपके करीब आये, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिये.....चाणक्य

सम्पादकीय

मुद्दों से भागते मोदी

क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जानबूझकर आम आदमी के मुद्दों से भागने का प्रयास कर रहे है? यह सवाल चुनाव के अन्तिम चरणों तक पंहुचते-पहुंचते एक बड़ा सवाल बन कर खड़ा हो गया है। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद मंहगाई और बेरोजगारी उसके बड़े मुद्दे बन जाते हैं। मंहगाई और बेरोजगारी के कारण उसे अपने और परिवार के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना कठिन ही नही असंभव तक हो जाता है। देश में मंहगाई जिस स्तर पर मई 2014 में थी आज उससे कम होने ही बजाये और ज्यादा ही बढ़ी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि मोदी और उनकी भाजपा ने 2014 में प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का जो वायदा देश को बेचा था वह एकदम कोरा और झूठा आश्वासन ही साबित हुआ है। उल्टे नोटबंदी के बाद करोड़ो लोगों का रोजगार छिन गया है। यहां तक की केन्द्र सरकार और उसके विभिन्न निकायों में लाखों पद रिक्त पड़े है जिन्हे मोदी सरकार भर नही पायी है। भ्रष्टाचार के जिन मुद्दों को 2014 में उछालकर यह धारणा बना दी गयी थी कि कांग्रेस और यूपीए सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन गयी है उनमें से एक भी मुद्दे पर किसी अदालत से किसी को कोई सज़ा मिल पाने की बात आज तक सामने नही आयी है। उल्टे यह सामने आया है कि जिस 1,76000 करोड़ के स्कैम में कई बड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी वह स्कैम हुआ ही नही था।

आज पांच वर्ष सरकार चलाने के बाद इन सभी मुद्दों पर सफल उपलब्धियों के साथ मोदी और उनकी सरकार को गर्व के साथ वोट मांगने आना चाहिये था। लेकिन ऐसा हो नही पाया है। चुनाव में मोदी इन मुद्दों पर बात ही नही आने दे रहे हैं। बल्कि पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र तक में भी उनका जिक्र नही है। बल्कि उज्जवला और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का भी इस चुनाव प्रचार अभियान में कोई उल्लेख सामने नही आया है जबकि एक समय इन योजनाओं के लाभार्थीयों के आंकड़ों के आधार पर बड़े-बड़े दावे किये जा रहे थे। ऐसे बहुत सारे वायदे और दावे हैं जो 2014 की सरकार बनने से पहले और बाद में किये गये थे। कायदे से आज के चुनाव में तो इन्ही वायदों/दावों से जुड़े आंकड़े जनता की अदालत में रखे जाने चाहिये थे लेकिन इस चुनाव में मोदी और उनकी सरकार इस सबका कोई जिक्र ही नही छेड़ रही है। जिस नोटबंदी से यह दावा किया गया था कि उसके बाद देश में टैक्स अदा करने वालों का आंकड़ा बढ़ा है आज उसका भी कोई जिक्र नही किया जा रहा है क्योंकि इस आंकड़े में भी कमी आयी है। आज टैक्स अदा करने वालों की संख्या कम हुई है। इस तरह इस चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के पास 2014 से लेकर अब तक कुछ भी बड़ा नही है जिसके दम पर सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ यह दावा कर सके उसके अमुक काम से आम आदमी को सीधे लाभ हुआ हो।

इस चुनाव के शुरू में प्रधानमन्त्री ने पुलवामा और फिर बालाकोट का जिक्र उठाया लेकिन यह चर्चा भी ज्यादा देर तक नही चल पायी। इसके बाद हिन्दुत्व को मुद्दा बनाया गया प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाकर। इसी के साथ जब कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के लिये बनाये गये विशेष सेना अधिकारी अधिनियम में संशोधन करने की बात की तब राष्ट्रवाद का मुद्दा उभारा गया। लेकिन अब गालियों को मुद्दा बनाकर यह आरोप लगाया कि विपक्ष उन पर जुलम कर रहा है। नितिन गडकरी ने इन छप्पन गालियों की वाकायदा सूची बनाकर जनता से आग्रह किया कि वोट देकर इस जुल्म का बदला लें। अब सैम पित्रोदा की 1984 के दंगो को लेकर आयी टिप्पणी को मुद्दा बनाकर पंजाब और दिल्ली में प्रदर्शन करवाये गये हैं। हिंसा कहीं भी हो उसकी निन्दा की जानी चाहिये और हिसां करने वालों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिये। लेकिन जब हम 1984 के दिल्ली के दंगो की याद करते हैं तो उसी के साथ पंजाब में एक दशक से भी अधिक समय तक चले आतंकवाद की भी याद आ जाती है। उस आतंकवाद में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके जख्म भी हरे हो जाते हैं पंजाब में 1967 से जनसंघ से लेकर आजतक भाजपा का अकालीयों के साथ सत्ता का गठबन्धन रहा है। लेकिन इस गठबन्धन ने आतंकवाद के दौरान हुई हत्याओं की कितनी निंदा की है इसे भी सभी जानते हैं उस दौरान पंजाब में रात के समय अन्य राज्यों की बसें तक नही चलती थी। बसों से उतार कर गैर सिखों को मारा गया है यही इतिहास का एक कड़वा सच है। बल्कि अकाली-भाजपा सरकार में जब राजोआना को फांसी देने की बात आयी थी और मुख्यमन्त्री बादल ने उस पर केन्द्र को साफ कहा था कि ऐसा करने से पंजाब के हालात बिगड़ जायेंगे। बदाल के इस वक्तव्य पर भाजपा सरकार में होकर मूक दर्शक बनकर बैठी रही थी। हमने पंजाब के आतंकवाद के जख्म सहे हैं जो आज मोदी के ब्यान के बाद ताजा हो गये हैं।

आज जब 1984 के दंगो के गुनहागारों को सज़ा की बात हो रही है तो क्या आतंकवाद के दोषीयों को भी चिन्हित करके उन्हे भी सजा नही मिलनी चाहिये? क्या 2002 के गुजरात के दंगो के लिये भी दिल्ली की तर्ज पर ही सजा नही होनी चाहिये? गुजरात दंगो को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस हरंजीत सिंह वेदी कमेटी की रिपोर्ट पर आज तक कारवाई क्यों नही हो रही है। यह रिपोर्ट 28 दिसम्बर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय में आ चुकी है। इसी तरह क्या समझौता ब्लास्ट में मारे 68 लोगों की हत्या के जिम्मेदारों को सजा नही मिलनी चाहिये?

ऐसे दर्जनो मामलें हैं जिन पर मोदी सरकार को ही देश को जवाब देना है और जवाब के लिये चुनाव से ज्यादा उपयुक्त समय और कुछ नही हो सकता। इसलिये यह सब पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

भयंकर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है भारत

गौतम चौधरी

नरम घरेलू उपभोग, स्थायी निवेश में धीमी वृद्धि तथा सुस्त निर्यात के कारण 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। यह बात वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने फरवरी महीने में 2018-19 की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7.20 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया था। सात प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर पिछले पांच साल की सबसे धीमी दर है।

दूसरी ओर सरकारी कंपनियों के हाल खस्ता हो रहे हैं। मसलन देश की नवरत्न कंपनी भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रही है और हालत यह है कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते तक देने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ रहे हैं। वहीं कंपनी इन दिनों कम नकदी भंडार (कैश रिजर्व) के संकट से भी गुजर रही है। देश की सबसे समृद्ध कंपनी ओएनजीसी का सितंबर 2018 में कुल 167 करोड़ रुपए का ही कैश रिजर्व था जबकि मार्च 2018 में यह रकम 1,013 करोड़ थी। ऐसा क्यों हुआ इसके लिए कई प्रकार की चर्चा हो रही है। इस प्रकार की स्थिति के लिए नरेन्द्र मोदी की सरकार को जिम्मेबार ठहराया जा रहा है। यही नहीं नहीं बीएसएनएल के 80 हजार कर्मचारियों के उपर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। कंपनी को बेचने की योजना बनाई जा रही है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाईन पर आर्थिक संकट के बादल पहले से मंडरा रहे हैं। सरकार के स्वामित्व वाली एक और पवन हंस नामक कंपी की भी स्थिति खराब हो गयी है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कह दिया है कि उनका वेतन भी अब अनियमित तरीके से दिया जाएगा क्योंकि कंपनी के पास पैसे का घोर अभाव है। यही हाल हिन्दुस्तान एरोनोटिक लि. का भी है। यहा के कर्मचारी भी पैसे-पैसे के लिए मोहताज हैं। निजी कंपनियों में भूषन इंडस्ट्री के बाद जेट एयरवेट के हालात बेहद खराब हैं। कंपनी बंद हो चुकी है और उसके लगभग 22 हजार कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। यदि गौर से देखें तो देश की आर्थिक स्थिति के बारे में ये सारी आर्थिक घटनाएं नया चित्र प्रस्तुत कर रही है।

वित्त मंत्रालय ने मार्च महीने के लिये जारी अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा है कि रेपो दर में कटौती तथा बैंकों की तरलता में सुधार के जरिये मौद्रिक नीति से आर्थिक वृद्धि को गति देने की कोशिश की गयी है। मंत्रालय ने कहा, ''ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष 2018-19 में देश की आर्थिक वृद्धि दर सुस्त पड़ी है। इस नरमी के लिये जिम्मेदार मुख्य कारणों में निजी उपभोग का सुस्त पड़ना, स्थायी निवेश में धीमी वृद्धि होना तथा निर्यात का सुस्त पड़ना शामिल है।'' हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि भारत अभी भी सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मंत्रालय ने चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर बदलने की जरूरत है। उसने कहा, ''2018-19 की चौथी तिमाही में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में गिरावट आयी है और इसके कारण निकट भविष्य में निर्यात में सुधार को लेकर चुनौती उपस्थित हो सकती है।''बाह्य मोर्चे पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और चालू खाता घाटा का अनुपात 2018-19 की चौथी तिमाही में गिरने वाला है। राजकोषीय घाटा भी केंद्र सरकार के लक्ष्य के नजदीक आ रहा है। मंत्रालय ने कहा कि 2018-19 में नरम मुद्रास्फीति के कारण रिजर्व बैंक के समक्ष मौद्रिक नीति आसान करने का विकल्प उपस्थित हुआ।

इधर नोटबंदी और जीएसटी के जरिए देश के छोटे और मझोले उद्योग धंधों को बर्बाद हो चुके हैं। बाजार में पैसे हैं नही और बाजार दम तोड़ रहा है। वहीं आभासी बाजारों ने देश के लगभग 9 करोड़ खुदरा कारोबारी को दुकान बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है। देश की नवरत्न कंपनी भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रही है और हालत यह है कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते तक देने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। वहीं कंपनी इन दिनों कम नकदी भंडार (कैश रिजर्व) के संकट से गुजर रही है।

पिछले कुछ महीनों में ओएनजीसी का नकदी भंडार में भारी कमी आई है। मार्च 2017 में ओएनजीसी की कैश रिजर्व 9,511 करोड़ था। जो सितंबर 2018 में 167 करोड़ रुपए रह गया। मतलब पिछले डेढ़ साल में ओएनजीसी के नकदी भंडार में 9,344 करोड़ रुपए की कमी आई। कंपनी अपने फंड का इस्तेमाल हाल के दिनों में ऋण का भुगतान करने में कर रही है।

केंद्र सरकार ने ओएनजीसी के कामकाज में हस्तक्षेप कर सिर्फ जीएसपीसी को ही नही बचाया है बल्कि देश का वित्तीय घाटा कम करने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम में सरकार की सारी की सारी 51.11 फीसदी हिस्सेदारी 36,915 करोड़ में खरीदने पर भी मजबूर किया। यह कीमत एचपीसीएल के बाजार मूल्य (उस दिन के शेयर की कीमत के आधार पर) से 14 फीसदी ज्यादा है। कंपनी ने पिछले साल मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) का भी अधिग्रहण किया है। हालांकि, नकद लेन-देन की वजह से इसमें भी अभी गतिरोध बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक तेल और प्राकृतिक गैस खनन का व्यवसाय में भारी जोखिम होता है। ऐसे में इस व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में कैश बैलेंस की जरूरत होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ओएनजीसी के पास कम से कम 5000 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व होना चाहिए।

ओएनजीसी के पूर्व निदेशक (वित्त) आलोक कुमार बनर्जी ने कहा कि 63 साल के ओएनजीसी के इतिहास में यह पहला मौका है जब कंपनी का कैश रिजर्व इस स्तर पर पहुंचा है। उन्होंने इस स्तिथि को खतरे वाला बताया है। उनके मुताबिक ये स्थिति खासकर एचपीसीएल और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अधिग्रहण की वजह से आई है। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ी जानकारी जरूरी है। यह कंपनी भी पहले अच्छी स्थिति में थी लेकिन जैसे ही गुजरात में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी इस कंपनी में लूट-खसोट प्रारंभ हो गयी। जानकार बताते हैं कि उन दिनों जब मोदी की सरकार गुजरात में हुआ करती थी तब इसी कंपनी के माध्यम से किसी को ऑब्लाईज किया जाता था। टेलिग्राफ के एक वरिष्ट पत्रकार ने बताया कि इस कंपनी को मोदी सरकार के नुमाइंदों ने चारागाह बना दिया था और कंपनी घाटे में चली गयी। इस कंपनी ने बड़े प्रभावशाली तरीके से अपना जाल बिछाया और जैसे ही नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार का गठन हुआ कंपनी को ओएनजीसी के साथ जोड़ दिया गया। इसके कारण ओएनजीसी पर अतिरिक्त भार बढ़ा और अब ओएनजीसी घाटे में चलने के लिए मजबूर हो रही है।

हालांकि फिलहाल आर्थिक मंदी का पूरा ठिकड़ा अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध पर फोड़ा जा रहा है लेकिन वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि घरेलू उपभोग में आयी कमी के कारण विकास दर में कमी आयी है। साथ ही आयात और निर्यात का संतुलन दिन व दिन बिगड़ रहा है। निजी क्षेत्र की कंपनियों पर भी दबाव पड़ रहा है। जो कंपनियां इमानदारी से कम कर रही थी उसे भी बैंक लोन देने में आना-कानी कर रही है जबकि फॉड कंपनियां पहले पैसा लेकर भाग चुकी है। इसलिए निजी कंपनियों पर भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इसके बाद जीएसटी का मामला इतना पेंचीदा बना दिया गया है कि खुदरा व्यापारी उससे बेहद परेशान हो रहे हैं। इधर आम चुनाव से पहले विगत 10 मार्च को सरकार ने एक अध्यादेश लाकर आपसी कर्ज को भी आमदनी घोषित कर दी। अब उस पर भी आयकर लगाने की बात कही गयी है। इससे पूरा का पूरा मध्य आर्थिक वर्ग के व्यापारी परेशान हैं। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है।

दूसरी ओर भारतीय समाचार माध्यमों के द्वारा देश के हालात ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि दुनिया के निवेशक यहां निवेश करने से परहेज करने लगे हैं। यही कारण है कि मोदी सरकार के दौरान देश में निवेश की गति बेहद कमजोर रही है। कमजोर निवेश के कारण रोजगार में भी कमी आयी और आर्थिक मामले में प्रगति का रिपोर्टकार्ड बेहद कमजोर रहा। यह चित्र भयाव है। यदि ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में देश की आर्थिक प्रगति 2 प्रतिशत तक भी जा सकती है। ऐसे में देश में कभी भी किसी भी समय आपसी लड़ाईयां संभव है। इससे देश के सेहत पर बुरा असर होगा।

मोदी ने छोटी काशी से जोड़ा भावुक रिश्ता

भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश की बड़ी काशी (बनारस) का लोकसभा चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हिमाचल की छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी लोकसभा सीट का चुनाव हो गया है। इस चुनाव को कड़ी प्रतिस्पर्द्धा में भाजपा के ही विधायक अनिल शर्मा ने डाल दिया जिनके बेटे आश्रय शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। मंडी क्षेत्र सुखराम शर्मा के परिवार का गढ़ माना जाता है लेकिन भाजपा ने नरेन्द्र मोदी की लहर में हिमाचल प्रदेश की चारों संसदीय सीटें जीत ली थीं। मंडी के मौजूदा सांसद राम स्वरूप को ही भाजपा ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 मई को मंडी के पडुल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। श्रीमोदी ने देर से पहुंचने पर जनता से माफी मांगी। मंडी के पहुल मैदान में श्री मोदी की तीसरी रैली थी। प्रधान मंत्री के रूप में वह दूसरा बार छोटी काशी पहुंचे थे। मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंडी से भाजपा उम्मीदवार श्री रामस्वरूप, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल, कैबिनेट मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, गोविन्द सिंह ठाकुर, राम लाल मारकंडा, कांगड़ा से प्रत्याशी किशन कपूर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती मौजूद थे। पूर्वमंत्री अनिल शर्मा मौजूद नहीं थे और वे वहां मौजूद होते तो अजीब लगता लेकिन श्री मोदी की सभा से यह संदेश भी साफ–साफ गया है कि हिमाचल भाजपा में अनिल शर्मा के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ है, शांताकुमार, प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर एक–दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मंडी क्षेत्र में भाजपा की यह एकता जरूरी थी और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पार्टी की एकजुटता को और मजबूत कर दिया है। इसी दिन हमीरपुर के ऊना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी राम लाल ठाकुर के समर्थन में जन सभा की थी। राहुल की रैली में भी कांग्रेस के नेता थे और भीड़ भी लेकिन जिस तरह श्री मोदी ने वहां के लोगों से रिश्ता जोड़ा और पहाड़ी भाषा में कहा आ हाउ बड़ी काशी रा आशीर्वाद लेने यानी मैं बड़ी काशी (मंडी) का आशीर्वाद लेने आया हूं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो कांग्रेस की जमकर खबर ली, सिख दंगे का उल्लेख किया। कांग्रेस को महा मिलावटी, अलगाववादियों से बात करने वाला बताया फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में राष्ट्रद्रोह कानून को खत्म करने का जिक्र किया। इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया। इसके बाद श्री मोदी हिमाचल की राजनीति पर आ गये। उन्होंने कहा परिवारवाद की जड़ें हिमाचल में भी मजबूत हुई हैं, भाजपा इन जड़ों को तोड़ कर रहेगी। उन्होंने कहा मनाली में पैरा ग्लाइडिंग ट्रेनर (प्रशिक्षक) रोशन ठाकुर से बड़ी बातें सीखीं। रोशन की बेटी ने मेडल जीते तो मेरे पास पहुंची। उसने कहाकि मैं रोशन की बेटी हूं। मेरा सीना गर्व से फूल गया। रोशन की बेटी ने मुझे बताया था कि हिमाचल में उड़ान का रोमांच कभी नहीं भूल सकती। मोदी ने कहा कि 23 मई को चुनावो के नतीजें आएंगे तो फिर एक बार मोदी सरकार। रोहतांग टनल के उद्घाटन के लिए मैं ही आ रहा हूं।

मोदी का यह विश्वास भरा संबोधन और जनता के बीच से आवाज आती है– अब की बार चौकीदार। श्री मोदी जनता से और अधिक भावुकता सें जुड़ते हैं। कहने लगे मैं जब भी आपके पास आता हूं तो पुराने दिनों में खो जाता हूं। दिल्ली से आने वाला था कि पता चला मौसम खराब है, हेलिकाप्टर उतरना मुश्किल होगा। मैंने मन में कहा कि अगर बिजली महादेव की कृपा होगी तो जरूर लैण्ड होगा। एक बार जब बिजली महादेव गया तो बारिश शुरू हो गयी। उस जमाने में आज जैसे रास्ते भी नहीं थे। बिना तैयारी के गया था। बारिश काफी जोर से हुई। कुछ दूरी पर चायवाले सज्जन थे। गर्म–गर्म चाय पीता रहा और पांच घंटे वहां रूका रहा। वो चाय वाला सज्जन आज भी इस चाय वाले को याद करता है। श्री मोदी ने कहा हिमाचली व्यंजन सेपो बड़ी की याद नहीं भूल सकता.....। इस तरह से बतियाने वाले नेता का जादू मतदाताओं पर नहीं चलेगा तो किसका जादू चलेगा?

10 मई को मोदी का मंडी में जनता को संबोधित करना भावनात्मक रिश्ता माना जा रहा है। पिछली बार 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब भी श्री मोदी ने मंडी में रैली की थीं। उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान श्री मोदी ने कहा था कि मौजूदा भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा से उनका नाता कृष्ण और सुदामा जेसा है। उन्होंने राम स्वरूप को अपना अभिन्न मित्र बताया था। उस चुनाव में मोदी की लहर चल रही थी और राम स्वरूप चुनाव जीत गये थे। राम स्वरूप को 362824 मत मिले थे। उनके मुख्य मुकाबले में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह थीं। प्रतिभा सिंह को 322968 मत मिले थे? इस प्रकार करीब 40 हजार वोटों से राम स्वरूप को जीत मिली थी। यहां पर राजपूत समुदाय के ही सबसे ज्यादा वोटर है। इसके बाद मंडी क्षेत्र में पंडितों की बहुलता है। पंडितों का नेतृत्व पंडित सुखराम शर्मा कर रहे हैं।

पंडित सुखराम शर्मा की राजनीति में पकड़ तो मजबूत रही लेकिन चर्चा में वे तब आये जब उनके घर से लाखों रूपये की नकदी बरामद हुई। पंडित सुखराम शर्मा का बयान आया था कि मुझे नहीं पता कि ये रूपये कौन रख गया। बहरहाल दाल में काला देखकर ही कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से हटा दिया था। सुखराम शर्मा बाद में भाजपा के साथ चले गये लेकिन अब फिर वे कांग्रेस के साथ जुड़ गये हैं। कांग्रेस ने उनके पौत्र आश्रय शर्मा को मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। ऐसा माना जा रहा था कि सुखराम शर्मा के कांग्रेस में जाने से समीकरण बदल गये। सुखराम शर्मा को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। मंडी लोकसभा क्षेत्र में 10 विधान सभा क्षेत्र शामिल हैं। हिमाचल में जब 2012 में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, इससे ठीक पहले पंडित सुखराम शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गये थे। इसके बाद मंडी क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर भाजपा का कब्जा हो गया था और एक सीट पर स्वतंत्र उम्मीदवार को विजयश्री मिली थी। मंड़ी के समीकरण संवेदनशील हैं क्योंकि मंडी की सदर सीट से सुखराम के बेटे अनिल शर्मा विधायक हैं। जयराम ठाकुर ने उन्हें मंत्री भी बनाया लेकिन अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा है। मंड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बन गये तो पार्टी के सामने धर्मसंकट खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कहने पर अनिल शर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसीलिए 10 मई को छोटी काशी पहुंच कर अपने मित्र रामस्वरूप व जयराम ठाकुर का हौसला बढ़ाया है। यहां पर सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मंडी जिले के ही श्री जयराम ठाकुर निवासी हैं। मंडी के ही सदर विधान सभा क्षेत्र से वे विधायक भी हैं। मौजूदा सांसद राम स्वरूप को टिकट दिलाने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भूमिका निभायी थी। इस सीट को लेकर मुख्यमंत्री कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्षेत्र की सभी विधान सभाओं का दौरा करके जन सभाएं भी कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 19 मई को चारों सीटों पर चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस प्रकार अपने संबोधन से वहां की जनता के साथ संवाद कायम किया, उसका प्रतिफल चुनाव नतीजों में भी दिखाई पड़ सकता है। **(हिफी)**

जल विद्युत परियोजनाओं के निमार्ण पर उठते सवाल

शिमला/शैल। 2019 के लोक सभा चुनाव में देश की दोनों प्रमुख पार्टियों, भाजपा व कांग्रेस, ने अपने घोषणापत्र में हिमालय के संरक्षण का जिक्र तो किया है, लेकिन हिमाचल जैसे हिमालयी राज्यों की एक बड़ी चिंता पर चुप्पी साधे हैं। ये है बड़ी विकास परियोजनाओं से उत्प्रेरित आपदाएं जिनमें प्रमुख हैं जल विद्युत् परियोजनाओं का अनियंत्रित और अंधाधुंद तरीके से निर्माण।

हिमाचल प्रदेश जैसे आपदा प्रवण राज्य में हाल ही में बिजली प्रोजेक्ट से जुड़ीं दो घटनाएँ सामने आई, कुल्लू में 100 Mw के सैंज प्रोजेक्ट की सुरंग में दरारें पड़ने की (3 मई, 2019) और 520 Mw पारबती प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में निरंतर रिसाव की (14 अप्रैल 2019)। इन दोनों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, सामुदायिक प्रतिनिधियों और पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्रीय नियामक निकायों को 8 मई को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन द्वारा बिजली प्रोजेक्टों के नियोजन, निर्माण, और प्रचालन के स्तर पर सुरक्षा और पर्यावरण के नियमों में हो रही लापरवाहीयों उजागर किया गया।

ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल में बांधो से संबन्धित शिकायत निवारण तंत्र और जवाबदेही की अनुपस्थिति, और दंडात्मक कार्यवाही के आभाव के बारे में केंद्रीय जल आयोग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और डैम सेफ्टी प्राधिकरण को सूचित किया गया। ज्ञापन के अनुसार 'ऐसी निगरानी और जवाबदेही व्यवस्था की अनुपस्थिति में हिमाचल प्रदेश में 2012 से 15 से ज़ादा दुर्घटनाएं हो चूकी हैं जिनके कारण घर, जान-माल, जंगल, और स्थानीय पारिस्थितिकी को भारी नुक्सान पंहुचा है।

परियोजनाओं के निर्माण के बाद हो रही ऐसी लापरवाही और राज्य स्तर पर अनिवार्य डैम सेफ्टी सेल के अभाव पर आपत्ति जताते हुए हुए ज्ञापन पिछले साल की बारिशों में किन्नौर में हुए के हादसे का वर्णन करता है, जहाँ काशंग प्रोजेक्ट के टनल से भारी मात्रा में पानी चेतावनी दिए बिना छोड़ दिया गया था, जिसके चलते जंगल ज़मीन का 17 करोड़ से अधिक का नुक्सान हुआ। इस हादसे के पश्चात, किन्नौर के DC की तरफ से परियोजना निर्माण करता HPPCL के मैनेजर को एक हलकी फुल्की चिठ्ठी भेजी गयी, जिसमें मामले की जांच करने के लिए मात्र 'निवेदन' किया गया है ।ज्ञापन में हस्ताक्षरकर्ता, हिमधरा पर्यावरण समूह, से वैष्णवी राठोड, कहती हैं, RTI से पाई गयी सूचना से स्पष्ट होता है की राज्य के डैम सेफ्टी प्राधिकरण के 2014 में गठन के बाद हुयी पहली मिटिंग के पश्चात फिर कभी बैठक नहीं की गयी और न ही काशांग के हादसे के बाद प्राधिकरण ने कोई भी स्वतंत्र जाँच पड़ताल या कार्यवाही की । आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा, सुरक्षा नियमों की अवहेलना की कीमत अक्सर प्रभावित क्षेत्र की जनता को चुकानी पड़ती है और किसी भी सरकारी विभाग या कंपनी की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रहती।

ज्ञापन में नियंत्रण एवं महालेखापरिक्षक (CAG) की 2017 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, प्रोजेक्ट के स्तर पर डैम सेफ्टी सेल भी अनुपस्थित होने का मुद्दा उठाया गया। हिमाचल के ऊर्जा निर्देशालय (DoE) द्वारा 2014 की अधिसूचना के अनुसार हर परियोजना में सुरक्षा सेल्ल बननाअनिवार्य किया गया था । CAG की यह रिपोर्ट जो बांधो की सुरक्षा अनुपालन की जांच करती है, यह भी लिखती है की भाखड़ा नंगल, लारजी और चमेरा (पहला चरण) प्रोजेक्टों में, 18 में से सिर्फ 9 सुरक्षा निरीक्षण हुए हैं, साथ ही एक भी ''रिस्क असेसमेंट स्टडी'' या सुरक्षा ऑडिट नही किया गया।

प्रोजेक्ट कंपनियों की अपारदर्शिता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए हिमधरा समूह से मान्शी आशर ने बताया कि अप्रैल 2017 में जब 800 Mw के पारबती (दुसरे चरण) परियोजना में लीकेज हुई थी, तब NHPC से विस्तृत जांच रपट की मांग की गयी थी। तब कंपनी ने यह जवाब दिया कि परियोजना की टेस्टिंग अभी जारी है, और यह सूचना तभी दी जा सकती है जब टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाये। इसमें आगे जोड़ते हुए, लीकेज से प्रभावित रेला गांव के मोती राम, जो हिमाचल किसान सभा, बंजार के सचिव है, कहते है, इस हादसे को हुए तीन साल हो गए है, और प्रोजेक्ट, जो की कई सालों से लंबित है, उसको कई भूवैज्ञानिक चुन्नोतियों का सामना करना पड़ा है जिसके चलते परियोजना अभी तक कार्यरत नहीं हो पायी है।

ज्ञापन के एक और जारीकर्ता, हिमलोक जाग्रति मंच, किन्नौर के आर. एस. नेगी कहते हैं हम सालों से यह महत्त्वपूर्ण बात उठाते आयें हैं कि परियोजनाओं के नियोजन के दौरान वास्तविक पर्यावरण प्रभाव आंकलन नहीं हो रहा है। इसके कारण परियोजनाएं ऐसी गलत जगह बनाई जा रही हैं जो पहले से ही भूस्खलन, भूकंप और अन्य आपदाओं से ग्रसित हैं। CAG कि रिपोर्ट भी इस पर प्रकाश डालते हुए काशांग प्रोजेक्ट का वर्णन करती है। रिपोर्ट कहती है कि निर्माणकर्ताओं ने 2.80 करोड़ रूपये कि बिल्डिंग बनाने से पहले वहां कोई सर्वे नहीं किया था, जिसके कारण यह बिल्डिंग जून 2013 के भूस्खलन में नष्ट हो गयी थी। इससे स्पष्ट होता है कि पर्यावरणीय, सामाजिक या आर्थिक नुकसान के इलावा इन परियोजनाओं को आर्थिक रूप से घाटा भी झेलना पड़ रहा हैं। जल विद्युत् परियोजनाओं से राजस्व लगातार गिर रहा है, और 2017-18 में यह सबसे नीचे 687 करोड़ रूपये तक गिर गया। आशर आगे कहती हैं, जहाँ सरकार को स्थानीय अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी को बचाना चाहिए, वहां सरकारी योजनाएं केवल इन खतरों की कीमत आम जनता पर डाल रही है।

एक स्वतंत्र जांच और सभी परिचालन परियोजनाओं के सुरक्षा अनुपालन के ऑडिट के अलावा, पिछले कुछ वर्षों में हुई बांध संबंधी सभी दुर्घटनाओं पर वैज्ञानिक अध्यन जारी करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। ज्ञापन में कुछ और प्रमुख मांगों में जनता द्वारा उठाये जा रहे मुद्दों की सुनवाई के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण, राज्य स्तर पर और हर परियोजना के भीतर स्वतन्त्र डैम सेफ्टी सेल को सक्रिय करना भी शामिल है, जिसके बिना किसी भी परियोजना का निर्माण या संचालन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बहुत बदलाव आया है:ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर

शिमला/शैल। ब्रिगडियर खुशाल ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि भारतीय सेना संसार की श्रेष्ठतम सेनाओं में से एक हैं भारतीय सेना ने दुनियाभर में कई लडाईयों और अभियानों में हिस्सा लिया है। भारतीय सेना का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक

खतरों से बचाव और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। हिमाचल का देश की आन बान के लिये मिटने वालों में नाम सबसे उपर रहता है। आजादी के बाद सेना में परम शौर्य के लिये दिये गये 21 परम वीर चक्र सम्मान मे से चार क्रमश: मेजर सोमनाथ शर्मा लैटिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बतरा व रायफलमैन संजय कुमार शामिल है। यही नही अन्य सैंकडो वीरता सम्मानों के साथ हिमाचल ने अपना मस्तक सदैव ऊचां कर रखा है। यहां पूव सैनिकों के 1 लाख 51 हजार परिवार हैं, व 1 लाख सैनिक सेवारत हैं साथ ही 2 लाख 50 हजार पैरा मिलिट्री सैनिक है। हिमाचल में सेना व अर्ध सैनिक बलों मे संख्या के हिसाब से क्रमश: कांगड़ा, हमीरपुर, मण्डी, बिलासपुर, ऊना कुल्लु व अन्य जिलों के सैनिक हैं। प्रदेश के करीब 20% परिवार किसी न किसी तरह सेना व अर्धसैनिक बलों से जुड़े हैं मेरे 35 साल से ज्यादा समय के सैन्य जीवन में ज्यादातर समय जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की लड़ाई में बीता। श्रीलंका व सिरालियोन में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सैन्य कारवाई(खुखरी) का मौका भी मिला जिस अभियान में 225 भारतीयों को विद्रोहियों से छुड़वाया गया था।

उन्होने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के बाद पहली बार युद्ध के बिना पिछले दो वर्षो में न केवल सेना ने लाईन ऑफ कन्ट्रोल को पार करके बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर ही नही बल्कि पाकिस्तान मे अंदर घुसकर आतंकियों को ठिकाने लगाकर दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति व मजबूत नेतृत्व का परिचय दिया है। अगर आज पीछे मुड़ कर देखा जाये तो सेना तो वही है उनकी बहादुरी व जज्बा भी वही है। परन्तु कूटनीतिक मोर्चे पर जितना मजबूत आज हम है उतना हम कभी नही थे।

ब्रिगडियर ने कहा कि यह मोदी सरकार की कूटनीतिक पहल का ही नतीजा है कि दोनों स्ट्राईक के बाद कोई प्रतिरोध कामयाब नही हुआ व अंतराष्ट्रीय समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ। चीन के वीटो के बाद अंतत: अजहर मसूद अतंराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हुआ। दिल्ली के इंडिया गेट पर बना शहीद स्मारक शहीद स्मारक प्रथम विश्वयुद्ध के शहीदों की स्मृति में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। मोदी सरकार द्वारा पहली बार आजादी के बाद हुए शहीदों की स्मृति में दिल्ली में राष्ट्रीय शहीद समारक बनाकर उनके बलिदान को सलाम करते हुये सेना व शहीदों का मान-सम्मान बढ़ाया है। वनरैंक वन पैंशन लागू करने में पहल करते हुए करीब 50 साल से लंबित चल रहे मामले को सुलझा कर लाखों पूर्व सैनिकों को उनका हक दिलाया है।

उन्होने बताया कि प्रदेश स्तर पर हिमाचल की जयराम सरकार ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये उनकी पैंशन 500 से बढ़ाकर 3000 रूपये कर दी है। हिमाचल के लोगों के सेना में योगदान को देखते हुए हिमाचल रेजीमेंट स्थापित करने के लिये पुरजोर मांग की जा रही हैं साथ ही हिमाचल का सेना में कोटा, जोकि जनसंख्या के अनुपात पर तय होता है हिमाचल के सेना में योगदान को देखते हुए उसे बढ़ाने पर अपना पक्ष जयराम सरकार द्वारा केन्द्र के समक्ष लगातार रखा जा रहा है। कीर्ती चक्र की सम्मान राशि को 1.5 लाख से बढ़कार 2 लाख किया गया। सेना में अधिकारी बनने की एसएसबी ट्रेनिंग राशि का 6000 से बढ़ाकर 12000 रूपये किया गया। पैराप्लेजिक विकलांग पूर्व सैनिकों की वार्षिक सहायता को 85000 रूपये बढ़ाकर 1 लाख किया गया।

ब्रिगडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि ये कांग्रेस की नाकामियां है कि कांग्रेस आज आतंकग्रस्त क्षेत्रों में सेना को प्राप्त विशेषाधिकार कानून ''अफस्पा'' को रिव्यू करके सेना के हाथ बांध कर आतंकी ताकतों को प्रश्रय देने का काम करना चाहती है। उन्होने कहा कि 1971 के युद्ध में सेना के शौर्य से जीती बाजी हम यहीं शिमला में टेबल पर हारे थे। जब हमारे पास 93000 युद्धबंदी थे परन्तु हम उनके बदले अपनी एक भी मांग नही मनवा सके। उन्होने कहा कि 1971 के युद्ध के बाद कांग्रेस सरकार ने सेना के शौर्य का इनाम देते हुए सेना के जवानों की पैंशन 70 % से 30% कर किया था और वनरैंक वन पैंशन को भी लागू नही किया।

दादा के आंसू पोते की नाव पार नहीं लगा सकते:महेन्द्र सिह ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार में वरिष्ठ मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि वंशवाद में फसे दादा सुखराम के घड़ियाली आंसू पोते आश्रय शर्मा की

पतवार नहीं बन पाएंगे। पहले सुखराम वर्षों तक अपने बुढ़ापे की दुहाई देकर जनता से वोट मांगते रहे। फिर उन्होंने अपने पुत्र के लिए आंसू बहाये। मण्डी की जनता ने इतना तक तो बर्दाश्त कर लिया। अपने परिवार के भंवर में फंसे बुजुर्ग नेता अब आंसुओं के सहारे पोते को भी संसद में भेजना चाहते हैं।

सिचाई एवं जनस्वास्थ्य और बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जब पूरा देश एक बार फिर नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ा है तो मण्डी की समझदार जनता खुद को मुख्यधारा से अलग-थलग कैसे रख सकती है। मण्डी के लोगों को बुजुर्ग दादा के आंसुओं की बजाये अपने संसदीय क्षेत्र और प्रदेश के विकास की परवाह है। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम जब खुद चुनाव लड़ते थे तो बात कुछ और थी। लेकिन उसके बाद बेटे और पोते के लिए मण्डी की जनता के हितों को चोट पहुंचाना सही नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने कहा कि वे निजी तौर पर पंडित सुखराम का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बढ़ती उम्र के कारण सुखराम का अपने परिवार के प्रति मोह जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि मण्डी संसदीय क्षेत्र और प्रदेश के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का क्या योगदान है? आश्रय शर्मा कोअ्र एक ऐसा मुद्दा बता दें जो कांग्रेस का टिकट मिलने से पहले उन्होंने मण्डी की जनता के हित में उठाया हो। चुनाव में हार के डर से कांग्रेस का कोई नेता टिकट लेने को तैयार नहीं था। इसलिए सुखराम ने आंसू बहाकर अपने पोते को टिकट दिलवा दिया।

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि यह बात मण्डी की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल को दिल खोलकर आर्थिक सहायता दी है। केन्द्र में दुबारा प्रधानमंत्री बनने पर मोदी फिर से हिमाचल को विकास के लिए आर्थिक मदद देंगे। इससे मण्डी की जनता का भी भला होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या दादा सुखराम के आंसू मण्डी की बुनियादी समस्याएं हल करने में सहायक हो सकते है? उनका कहना है कि पांच साल तक लगातार जनता की सेवा करने वाले ईमानदार सांसद रामस्वरूप एक बार फिर भाजपा की ओर से मैदान में उतरे हैं। उनको दिया गया एक-एक वोट सीधे मोदी तक पहुंचेगा। जबकि सुखराम के घड़ियाली आंसू पिछली बार सिर्फ 44 सीटें जीतकर विपक्ष के नेता का दर्जा तक हासिल न कर पाने वाले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि इस बार फिर जनता ने राम स्वरूप को संसद में पहुंचाने का मन बना लिया है।

जंगलों को आग से बचाने के लिए जल्द बनेगी क्विक रिस्पांस टीम :मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव बी. के.अग्रवाल ने प्रदेश में वनों को आग से बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा बारे आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनों को आग से निपटने के लिए 'त्वरित रिसपांस टीम' (क्विक रिस्पांस टीम) का गठन किया जाएगा जो गृह रक्षकों की मदद से वनों की आग को बुझाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 80 संवेदनशील वन डिवीजनों में चौबीस घंटे फॉरेस्ट स्टॉफ के अतिरिक्त विभाग के कर्मचारी वनों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि त्वरित रिसपांस टीम बिना किसी विलम्ब के आपातकाल में वनों की आग से सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होगी।

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में 196 फॉरेस्ट रेंज हैं जिनमें से 80 वन परिक्षेत्र आग की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के साथ लगने वाले वन क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड को हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। होमगार्ड को अग्निशमन किट तथा अग्नि प्रतिरोधक वर्दी को हमेशा तैयार रखने को कहा गया है।

बी.के.अग्रवाल ने वन अधिकारियों को नई तकनीक तथा तरीकों के साथ जंगल की आग बुझाने के लिए स्थानीय लोगों के पारम्परिक तरीकों का भी पता लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने में मदद करने पर उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने वन नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर क्रमश: 1077 तथा 1070 को प्रदेश तथा जिला आपदा प्रबन्धन के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर के साथ जोड़ने के निर्देश दिए। यह दूरभाष नम्बर वनों में लगने वाली आग की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) राम सुभग सिंह ने इस अवसर पर कहा कि वन इस प्रदेश की अमूल्य धरोहर हैं, जिसकी सुरक्षा तथा संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। त्वरित रिसपांस टीम (क्विक रिस्पांस टीम) का गठन तथा अन्तर विभागीय सहयोग प्रदेश के जंगलों की सुरक्षा तथा संरक्षण के

लिए अह्म भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 30 अप्रैल, 2018 तक 122 वनों की आग के मामले सामने आए थे जबकि इस वर्ष 8 मई तक वनों की आग के केवल 27 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 28 अग्नि संवेदनशील वन मण्डलों में इस मौसम में एक वाहन पानी की टंकियो, लिफ्टिंग मोटर तथा पाइप के साथ उपलब्ध करवाया गया है तथा दूसरा वाहन अतिशीघ्र उपलब्ध करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वनों की आग से सुरक्षा बारे लोगों को जागरूक करने के लिए चार वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हैं। प्रदेश आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से प्रदेश के 11 जिलों के 68 क्षेत्रों में वनों की आग से सुरक्षा बारे इस वर्ष 22 मार्च से 30 मार्च, 2019 तक जनजागरण अभियान चलाया गया।

पीसीसीएफ अजय शर्मा ने बताया कि फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के साथ रैपिड फोरेस्ट फायर फोर्स को पंजीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से 11000 से अधिक स्वयसेवक, गैर सरकारी संगठन तथा पीआरआई के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में जंगल की आग बारे अलर्ट का एसएमएस प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा देश में सबसे अधिक है तथा निकट भविष्य में इसकी संख्या 20 हजार से अधिक होने की सम्भावना है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अनिल खाची, विशेष सचिव राजस्व व आपदा प्रबन्धन डी.सी. राणा, संयुद्र सचिव वन सत्तपाल धीमान वन संरक्षण एवं अग्नि नियंत्रण अशोक चौहान तथा पुलिस, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्मार्ट मोबाईल फोन क्रांति से साईबर अपराध को मिल रहा बढ़ावा

शिमला/शैल। स्मार्ट फोन साईबर अपराधियो के लिए गोल्ड माईन का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में इन्टरनैट सेवा का अधिकतर उपयोग भारत वर्ष में लोग स्मार्ट मोबाईल फोन के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। आज स्मार्ट फोन के

माध्यम से उपभोग्ता विभिन्न मोबाईल एपलीकेशनस व कई फर्जी एप पले स्टोर से डाउनलोड करके रखते है जिससे उपभोगताओं की निजी सूचना व अन्य डॉटा आसानी से साईबर अपराधियों की पहुंच में आ जाता है जिसमें कई खेल एप जैसे फोरनाईट जिसके विश्व भर में 200 मिलियन से अधिक खिलाडी है। इसके अलावा वितिय लेन देन के लिये भी कई तरह के एपलीकेशन पले स्टोर पर हैं और कई फेक एप भी मिलते जुलते नाम से आज मिल जायेंगे जो कि देखने में सही प्रतीत होते है जो कि उपभोगता से इनस्टाल करते समय बहुत सी अनुमतियां जैसे कि रीड एण्ड सैण्ड एस एम, वयू गैलरी और वयू कानटैक्ट डीटेल को अलॉव करने के लिए कहते है जो कि बाद में अनुमति होने के कारण हैक्कर इन अनुमतियों का फायदा उठा कर निजी जानकारी व डाटा प्राप्त कारण फ्रॉड करने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आज के उपभोक्ताओं को स्मार्ट फोन की सही जानकारी ना होने के कारण यह स्मार्ट फोन ही साईबर अपराधियों के लिए गोल्ड माईन बन गया है। इस लिये उपभोगताओ से अनुरोध है कि उपरोक्त डाटा चोरी से बचने के लिए अपने स्मार्ट फोन में जन्यूइन एपलीकशन व जन्यूइन मोबाइल फोन एंटीवायरस ही इनस्टॉल करें तथा किसी भी एपलीकशन को इनस्टॉल करते समय क्या-क्या परमीशनज अलॉव करनी है उन्हें जरूर पढ़ लें।

राज्य साईबर क्राईम पुलिस थाना शिमला द्वारा साईबर क्राईम पीडित व्यक्तियों कि शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही की जा रही है इस वर्ष 2019 में अभी तक 29 साईबर क्राईम पीडित व्यक्तियों की शिकायत पर कुल 3,70,000/- रु पीडित के खाते में साईबर अपराधियों के खातों से रिफन्ड करवाये गये हैं और अन्य शिकायतों पर कार्यवाही का जा रही है। शिकायतकर्ताओं से भी विभाग का अनुरोध है कि वह तुरन्त साईबर अपराध की सूचना पुलिस व संबधित बैंक को दे। इस बारे में लोगों को सोशल मिडिया के माध्यम से भी जागरुक किया जा रहा है।

13 मई को भारत में मनाया जाएगा फालुन दाफा दिवस

शिमला/शैल। 13 मई का दिन पूरे विश्व में फालुन दाफा अभ्यासियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। फालुन दाफा मन और शरीर का एक

उच्च स्तरीय साधना अभ्यास है जिसे गुरु ली होंगजी ने 13 मई, 1992 में चीन में सार्वजनिक किया। सत्य-करुणा-सहनशीलता के तीन सिद्धांतों का रोजमर्रा की जिंदगी में पालन करना सिखाया जाता है। आज दुनिया भर में 120 से अधिक देशों में 10 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा इसका अभ्यास किया जा रहा है। फालुन दाफा और इसके संस्थापक, श्री ली होंगजी को, दुनियाभर में 1,500 से अधिक पुरस्कारों और प्रशस्तिपत्रों से नवाजा गया है। श्री ली होंगजी को नोबेल शांति पुरस्कार व स्वतंत्र विचारों के लिए सखारोव पुरस्कार के लिए भी मनोनीत किया जा चुका है।

शिक्षाओं के अतिरिक्त, फालुन दाफा में पांच व्यायाम भी सिखाये जाते हैं जो गति में धीमे, सौम्य और ध्यान पर आधाारित हैं। व्यायाम सीखने में सरल किन्तु प्रभावशाली हैं और पूरी तरह नि:शुल्क सिखाये जाते हैं। आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में फालुन दाफा का अभ्यास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रभावी रहा है, बल्कि, इसने करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक विकास और नैतिक चरित्र के उत्थान में भी सकारात्मक भूमिका प्रदान की है।

फालुन दाफा को भारत में फालुन गोंग भी कहा जाता है, को भारत में सन 2000 से सिखाना आरम्भ किया गया था। तब से, देश भर के अनेकों स्कूल और कॉलेजों में इस ध्यान अभ्यास को सिखाया गया है। कई बड़े संगठनों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों लिए फालुन दाफा की कार्यशालाएं आयोजित की हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई जेल अधीक्षकों ने कारागृहों में कैदियों के स्वास्थ्य और नैतिक गुण उत्थान के लिए इस अभ्यास को सिखाने के लिए अनुरोध किया है। मुंबई के अनेक फैशन मॉडल्स भी अपने भागदौड़ भरे जीवन में स्थिरता और तनावमुक्ति के लिए फालुन दाफा को अपना रहे है।

चीन में 1992 में सार्वजनिक होने के बाद से, फालुन गोंग ने लोगों द्वारा अनुभव किए गए स्वास्थ्य लाभ और नैतिक मानकों में सुधार के कारण चीनी लोगों के बीच बेहद लोकप्रियता प्राप्त कर ली। कुछ वर्षों में, करीब 7 करोड़ चीनी लोग लगातार इसका अभ्यास करने लगे। सरकार और सशस्त्र बलों के कई उच्च पदाधिकारी भी उन लोगों में से थे जिन्होंने इस अभ्यास को अपनाया।

इसका बढ़ता जनाधार चीनी शासकों को खलने लगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने फालुन दाफा की शांतिप्रिय प्रवृति के बावजूद इसे अपने प्रभुसत्ता के लिए खतरा माना और 20 जुलाई 1999 को इस पर पाबंदी लगा दी और इसे कुछ ही महीनों में जड़ से उखाड़ देने की मुहीम चला दी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी फालुन गोंग को दबाने के लिए क्रूर दमन कर रही है जो आज तक जारी है।

दुनिया भर के फालुन दाफा अभ्यासी इस दिवस को गरिमापूर्वक मनाते हैं और रैलियों, प्रदर्शनियों और सम्मेलनों का आयोजन करते है। भारत के फालुन दाफा अभ्यासी भी इसकी 27वीं वर्षगाँठ के अवसर पर 13 मई को अनेक शहरों में कार्यशालाओं, व्यायाम प्रदर्शन और गोष्ठियों का आयोजन कर रहे है। फालुन दाफा सीखने या इसके बारे में अधिक जानकारी के लिये www.falundafa.org या www.falundafaindia.org पर पा सकते हैं।

रोहतांग टनल और दर्रे से 2833 लोगों ने घाटी में किया प्रवेश:चौधरी

शिमला/शैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल-स्पीति, अश्वनी कुमार चौधरी ने कहा कि अप्रैल माह से लाहौल घाटी में अब तक रोहतांग दर्रे और रोहतांग टनल से 2833 स्थानीय लोगों ने प्रवेश किया है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष अत्याधिक बर्फवारी के चलते रोहतांग दर्रा से यातायात सुविधा आरंभ ना हो पाने के चलते अभी तक लाहौल घाटी सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पायी है। जिससे लोगों को घाटी में आवाजाही में

दिक्कत आ रही थी।

उन्होंने कहा कि लोगों को घाटी में लाने के लिए जिला प्रशासन ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से सामान्जस्य बैठाकर रोहतांग टनल से भी लोगों को चरणबद्ध तरीके से घाटी में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घाटी के सभी मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए घाटी पहुंच सकें यह सुनिश्चित किया जा रहा है तथा जिला प्रशासन लगातार सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के संपर्क में है।

चौधरी ने बताया कि रोहतांग टनल से अप्रैल माह से 1177 तथा रोहतांग दर्रे से अभी तक 1656 लोग यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग तथा प्रवासी मजदूरों की आवाजाही रोहतांग दर्रे से पैदल भी जारी है और घाटी में पैदल आने वाले लोगों की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए कोकसर में बचाव दल चौकी तैनात की गई है। उन्होंने कोकसर का दौरा कर बचाव दल के लोगों से पैदल आने वाले लोगों की जानकारी हासिल की। उन्होंने कोकसर में बचाव दल टीम के कार्य की सराहाना की और कहा कि कोकसर में बचाव दल चौकी रोहतांग दर्रे से सड़क मार्ग खुलने तक कार्यशील रहेगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

क्या कांग्रेस 2014 की हार का बदला ले पायेगी वीरभद्र की सक्रियता के बाद उठी चर्चा

शिमला/शैल। जैसे-जैसे चुनाव प्रचार अपने अन्तिम पड़ाव तक पंहुचता जा रहा है उसी अुनपात में कांग्रेस और विशेषकर वीरभद्र सिंह की प्रचार में सक्रियता बढ़ती जा रही है। जबकि एक समय तक भाजपा और वीरभद्र के अन्य विरोधी उनकी कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर की जा रही टिप्पणीयों से यह प्रचार करते जा रहे थे कि वीरभद्र स्वयं कांग्रेस को हराने का खेल रच रहे हैं। इसके लिये तर्क दिया जा रहा था कि प्रदेश के चारों कांग्रेसी उम्मीदवार वीरभद्र की पंसद के नही हैं। कहा जा रहा था कि वीरभद्र कांगड़ा में सुधीर शर्मा, हमीरपुर में राजेन्द्र राणा के बेटे की वकालत कर रहे थे और मण्डी में तो सुखराम उनके धुर विरोधी रहे हैं इसलिये वह उनके पौत्र को आर्शीवाद नही देंगे। शिमला क्षेत्र में तो उनके अपने विधानसभा हल्के अर्की और विक्रमादित्य के शिमला ग्रामीण तक में कांग्रेस के हारने के कयास लगाये जा रहे थे।

लेकिन प्रदेश की राजनीति को समझने वाले विश्लेषक जानते हैं कि प्रदेश के चार बड़े नेता वीरभद्र, सुखराम, शान्ता कुमार और प्रेम कुमार धूमल राजनीति के जिस मुकाम तक पंहुच चुके हैं वह स्थान उन्होने अपनी मेहनत से हासिल किया है और उसे वह अन्तिम पड़ाव पर आकर खोना नही चाहेंगे। इसलिये सुखराम ने वीरभद्र से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना कर ली। इस क्षमा याचना के बाद वीरभद्र का सम्मान और बढ़ा है। इस सम्मान को बनाये रखने के लिये वह आश्रय को अपना पूरा आर्शीवाद देने में कोई कसर नही छोडेंगे यह स्वभाविक है। क्योंकि जिस ऐज-स्टेज पर वीरभद्र पंहुच चुके हैं उससे यह लगता है कि वह 2022 का चुनाव नही लड़ना चाहेंगे क्योंकि सहेत का तकाजा रहेगा। ऐसे में जब आज वह कांग्रेस के मसीहा होने के मुकाम पर हैं तो इसे वह खोना नही चाहेंगे। फिर ऊना की रैली में जिस तरह से राहुल गांधी ने उन्हे सम्मान दिया है उससे भी यही स्पष्ट होता है। फिर जब 2014 में भाजपा ने चारों सीटों पर मोदी लहर के चलते कब्जा कर लिया था तब वीरभद्र ही प्रदेश के मुख्यमन्त्री थे। मण्डी से उनकी पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह उम्मीदवार थी और मण्डी शुरू से ही उनका चुनाव क्षेत्र रहा है। वीरभद्र 2014 के बाद 2017 तक मुख्यमन्त्री रहे हैं। आज जयराम को तो अभी एक वर्ष ही हुआ है मुख्यमन्त्री बने और फिर इस बार मोदी के नाम की लहर वैसी ही है जैसी 2004 में शाईनिंग इण्डिया की थी। इस परिदृश्य में सुखराम और वीरभद्र के इकक्ठा होने से न केवल मण्डी ही बल्कि पूरे प्रदेश का परिदृश्य बदल जाता है। इस परिदृश्य में सुरेश चन्देल का कांग्रेस में शमिल होना पार्टी की स्थिति को और मजबूत कर देता है।

अब शिमला जिला में जिस तरह से वीरभद्र कुलदीप राठौर और विक्रमादित्य ने मिलकर दौरा किया है उससे स्थिति पूरी तरह बदल गयी है। बल्कि अब जिस तरह से सुरक्षा कारणों का हवाला देकर प्रियंका गांधी की शिमला जिला की रैली और रोड़ शो की सरकार ने अनुमति नही दी है उससे भाजपा की घबराहट ही सामने आती है। इस रैली और रोड़ शो को स्थगित करवाने से सरकार की छवि को ही नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ सुरेश चन्देल और सुखराम के कांग्रेस में शामिल होने का बदला लेने के लिये भाजपा ने सिंघी राम को तोड़कर भाजपा में शामिल करवाया है इससे कांग्रेस को कोई ज्यादा नुकसान नही पंहुच पाया है बल्कि इससे यही संदेश गया है कि भाजपा यह बदला तो लेना चाहती है लेकिन इसमें सफल नही हो पायी है।

आज कांग्रेस को सबसे बड़ा लाभ उसके चुनाव घोषणा पत्र में घोषित योजनाओं से मिल रहा है। कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत जो गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 72000 की आय सुनिश्चित करने का वायदा किया है वह सन्देश आम तक पंहुच चुका है। इस योजना पर कांग्रेस काफी समय से काम कर रही थी। इसके लिये हर प्रदेश से आंकड़े लिये गये थे। हिमाचल से भी ऐसे 1.50 लाख परिवारों को चिन्हित करके उनके वाकायदा फार्म भरकर कांग्रेस के केन्द्रिय कार्यालय को बहुत अरसा पहले से भेजे जा चुके हैं। इस न्यूनतम आय गारंटी योजना के साथ युवाओं को रोज़गार और किसानों के लिये अलग बजट कुछ ऐसे वायदे हैं जिनकी कोई काट भाजपा के पास नही है। फिर किसान ऋण माफ करने का वायदा जिस तरह से मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें बनने के बाद सभी कांग्रेस शासित राज्यों में पूरा किया गया है उससे कांग्रेस के घोषणा पत्र की विश्वसनीयता और बढ़ी है। क्योंकि कांग्रेस के इन वायदों की तुलना भाजपा द्वारा 2014 में किये वायदों से की जा रही है। भाजपा इन वायदों की चुनाव प्रचार में चर्चा तक नही छेड़ पायी है और यहीं पर कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ रही है।

इस बार इन चुनावों में वाम दलों का मण्डी के अतिरिक्त और कहीं कोई उम्मीदवार नही है। ऐसे में वाम दलों के समर्थकों का भी कांग्रेस को लाभ मिलना स्वभाविक है क्योंकि सीपीएम नेता सीता राम येचुरी की रामायण को लेकर की गयी टिप्पणी के बाद भाजपा और वाम दलों का वैचारिक मतभेद और तेज हुआ है। फिर कांग्रेस ने अपना पूरा चुनाव आम आदमी के मुद्दों और बड़े उद्योगपतियों के बढ़ते भ्रष्टाचार बैंकों के इस कारण से बढ़ते एनपीए पर केन्द्रित कर रखा है। जबकि भाजपा पूरी तरह मुस्लिम और पाकिस्तान के डर पर अपने को केन्द्रित किये हुए है। जबकि यह केवल सत्ता के मुद्दे हैं आम आदमी के नही। इस तरह जब पूरे परिदृश्य पर नजर डाली जाये तो आम आदमी के संद्धर्भ में कांग्रेस का पलड़ा भारी पड़ता नजर आता है माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर से मिले फीडबैक ने उन्हे यहां एक जुट होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

नड्डा का प्रदेश के चुनाव प्रचार से बाहर रहना संयोग या कोई बड़ी रणनीति

शिमला/शैल। केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा की प्रदेश के चुनाव में इस बार ज्यादा सक्रिय भूमिका नही रह पायी है जबकि वह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। यहां तक चर्चा है कि शाह के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। इस पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए यह स्वभाविक है कि प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिये जितना अधिक समय वह देंगे उससे पार्टी को लाभ ही मिलेगा क्योंकि वह हिमाचल से ही हैं बिलासपुर उनका अपना जिला है। लेकिन इसी जिले से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तीन बार सांसद रहे सुरेश चन्देल इन चुनावों में कांग्रेस में शामिल हो गये हैं। सुरेश चन्देल जब भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे तब तक बिलासपुर के कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं का सोशल मीडिया में यह नारा ''नड्डा तुझसे बैर नही अनुराग तेरी खेरी नही'' काफी चर्चा का विषय बना रहा है। नड्डा प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं लेकिन उनकी सांसद निधि का बहुत बड़ा भाग हमीरपुर के नादौन ब्लॉक में बंटा है। नादौन से भाजपा के विजय अग्निहोत्री एक बार विधायक रह चुके हैं। 2017 का चुनाव हारने के बाद वह हमीरपुर जिले से पार्टी अध्यक्ष बना दिये गये है। नड्डा की सांसद निधि के वितरण के जो आंकड़े आरटीआई के माध्यम से बाहर आये हैं उनके मुताबिक अग्निहोत्री को नड्डा की सबसे अधिक स्पोर्ट हासिल है। अग्निहोत्री के रिश्ते धूमल के साथ कोई बहुत अच्छे नही माने जाते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही ऊना जिला आता है। ऊना के पूर्व विधायक सतपाल सत्ती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन सत्ती प्रदेश भाजपा के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हे अपने ब्यान के लिये चुनाव आयोग का 48 घन्टे का चुनाव प्रचार प्रतिबन्ध सहना पड़ा है। सत्ती ने राधा स्वामी संतसग ब्यास के अनुयायीयों को लेकर जो टिप्पणी की थी उसकी नाराज़गी इस समुदाय के लोगों में अभी तक शान्त नही हुई है। राधा स्वामी समुदाय का हमीरपुर और कांगड़ा के संसदीय क्षेत्रों में बहुत प्रभाव है और चुनावों में इनकी नाराजगी भारी पड़ सकती है।

इस समय प्रदेश में चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री जयराम पर है। वही इस समय पूरी बागडोर संभाले हुए हैं और पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। उनके अपने गृह जिले और संसदीय क्षेत्र मण्डी से ताल्लुक रखने वाले पंडित सुखराम कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं और उनका पौत्र आश्रय शर्मा यहां से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। आश्रय के पिता अनिल शर्मा जयराम के ऊर्जा मंत्री थे। इनका मन्त्रीपद जयराम ने आश्रय के कांग्रेस का उम्मीदवार बनने के बाद छीना है। पंडित सुखराम केन्द्र में दूर संचार मन्त्री रहे हैं और इस नाते दूर संचार की जो सुविधा /सेवा उन्होने प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाई है उसके लिये प्रदेश में उनका एक अपना अलग स्थान बन चुका है। 2017 में मण्डी जिले की दस में से नौ सीटें भाजपा ने उन्ही के सहारे जीती हैं यह सब मानते हैं। ऐसे में चुनावों के वक्त पर सुखराम और सुरेश चन्देल का भाजपा को छोड़कर जाना पार्टी और जयराम दोनों के लिये नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि सभी ने अपनी उपेक्षा होने का आरोप लगाया है। सरकार बनने के बाद सबके मान सम्मान का ख्याल रखना मुख्यमन्त्री की अपनी जिम्मेदारी बन जाता है और इसमें निश्चित रूप से जयराम काफी कमजोर साबित हुए हैं।

सरकार बनने के बाद जयराम के अपने चुनाव क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय को लेकर जो विवाद उठा था उस विवाद में धूमल और जयराम के राजनीतिक रिश्तो में दरार आ गयी थी। इस विवाद को हवा देने में धूमल का नाम लग गया था। यह नाम लगने पर धूमल को यहां तक कहना पड़ गया था कि सरकार चाहे तो इसमें सीआईडी से जांच करवा ले। विधानसभा का चुनाव धूमल को नेता घोषित करके लड़ा गया था। लेकिन संयोगवश धूमल स्वयं और उनके कई अन्य विश्वस्त चुनाव हार गये। लेकिन इस हार के वाबजूद विधायकों का बहुमत उनको मुख्यमन्त्री बनाना चाहता था। दो विधायकों ने तो उनके लिये सीट छोड़ने की ऑफर कर दी थी। धूमल की हार के बाद मुख्यमन्त्री पद के लिये नड्डा का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। नड्डा के समर्थक पूरी तरह तैयार होकर आ गये थे। लेकिन जयराम के जयपूर संबंधो ने सारा खेल बदल दिया। इस गेम में भले ही जयराम जीत गये लेकिन इसमें जो विसात बिछ गयी थी अभी तक सीमटी नही है। सभी अपना-अपना दांव खेलने की फिराक में हैं। क्योंकि पार्टी के अन्दर न केवल जयराम के समकक्ष ही कुछ लोग हैं बलिक कई उनसे वरिष्ठ भी हैं। फिर मुख्यमन्त्री बनने की ईच्छा तो हर विधायक और सांसद में होना स्वभाविक है। अपनी ईच्छाओं को रणनीतिक सफलता देने के लिये चुनावों से ज्यादा अच्छा अवसर कोई नही होता है यह सब जानते हैं।

कांगड़ा में शान्ता कुमार इस बार चुनाव लड़ना चाहते थे यह सर्वविदित है लेकिन जिस ढंग से उन्हें चुनाव से हटाया गया है उसकी पीड़ा वह जगजाहिर कर चुके हैं। शान्ता कुमार ने भी सोनिया गांधी की 2004 की शाईनिंग इण्डिया टिप्पणी का समर्थन किया है। इस समर्थन के भी राजनीतिक मायने अलग हैं। इसी तरह सोफत के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके विश्वस्त पवन ठाकुर द्वारा बिन्दल के खिलाफ उच्च न्यायालय में याकिचा दायर किये जाने को भी राजनीतिक हल्को में जयराम के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह कथन कि अब हर पांच साल बाद सरकार बदल जाती है तथा राम माधव का यह कहना कि भाजपा सहयोगीयों के साथ मिलकर सरकार बना लेगी और गडकरी का यह कहना कि अगला प्रधानमन्त्री भाजपा का नही बल्कि एनडी का होगा यह वक्तव्य अपने में बहुत कुछ कह जाते हैं। क्योंकि जब शीर्ष से भी ऐसे अस्पष्ट से ब्यान आने लग जाते हैं तब बार्डर लाईन पर बैठे हुए विरोधीयों और विद्रोहीयों को खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है। राजनीतिक विश्लेषको की नजर में इसमें जयराम प्रदेश में इसी दौर में से गुजर रहे हैं और इससे उनका आने वाला राजनीतिक सफर काफी कठिन हो सकता है।

इस परिदृश्य में नड्डा की भूमिका को लेकर प्रदेश के राजनीतिक हल्कों में सवाल उठने स्वभाविक हैं क्योंकि नड्डा को प्रदेश के मुख्यमन्त्री के पद के लिये जयराम से ज्यादा बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इस दावेदारी के चलते नड्डा का प्रदेश के चुनाव से बाहर रहना नड्डा और जयराम दोनों की अपनी अपनी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन अब जब अमितशाह ने चुनाव जीतने के बाद अनुराग को बड़ी जिम्मेदारी देने की घोषणा कर दी है तब अनुराग का नाम भी नड्डा और जयराम के साथ प्रदेश के बड़े पद के लिये जुड़ जाता है। ऐसे में एक और दावेदार का खड़ा हो जाना पूरे राजनीतिक परिदृश्य और जटिल बना देता है। इसलिये माना जा रहा है कि अपरोक्ष में छिड़ी दावेदारों की यह जंग इस चुनाव में पार्टी की सफलता पर ग्रहण का कारण न बन जाये।

अदाणी प्रकरण में

.....पृष्ठ 1 का शेष

रही है। मामला विजिलैन्स तक गया था। विजिलैन्स की जांच में पाया गया कि ब्रेकल ने गलत ब्यानी की है उसके खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की संस्तुति हुई थी। लेकिन आपराधिक मामला चलाने की बजाये फिर सरकार ने ब्रेकल के प्रति नरमी दिखायी। ब्रेकल के नाम पर 280 करोड़ अदानी ने सरकार को दे दिये। जबकि अदानी अधिकारिक तौर पर इसमें कहीं आता ही नही था। रिलायांस इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले गया। सरकार का इसमें 2713 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस नुकसान की भरपायी के लिये ब्रेकल को नोटिस तक देने की बात हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय में यह सारा कुछ रिकार्ड पर आ चुका है। लेकिन यह सब होने के बावजूद 280 करोड़ जो सरकार के पास ब्रेकल के नाम पर आ चुका है उसे जब्त करने की बजाये 18% ब्याज सहित उसे लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में धूमल वीरभद्र और अब जयराम सरकार की भूमिका भी सन्देह के घेरे में आ गयी है। क्योंकि महाधिवक्ता के अदालत में ब्यान से जयराम सरकार की मंशा भी यही हो जाती है कि वह यह पैसा लौटाना चाहती है। लेकिन कानूनी तौर पर यह पैसा लौटाना आसान नही होगा। इसलिये जब उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता का मामले को मन्त्रीमण्डल में ले जाने का आश्वासन आया तो प्रधान सचिव ऊर्जा ने इसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमन्त्री को फाईल पर यह अवगत करवाया है कि महाधिवक्ता को अदालत में यह कहने के निर्देश उन्होने नही दिये हैं। प्रधान सचिव के इस स्टैण्ड से इसकी जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता पर आ जाती है।